अब इलेक्ट्रिक कार से चलेंगे सीएम

सीएम के कारकेड में महिंद्रा की ईव्ही एसयूवी शामिल

▶ सीएम हाउस से स्टेट हैंगर तक ईव्ही में ही गए सीएम

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जून. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कारकेड में बुधवार से ईव्ही वाहन शामिल हो गया है. सीएम बुधवार को राजधानी से दिल्ली रवाना हुए. दिल्ली जाने के लिए उन्होंने सीएम हाउस से स्टेट हैंगर तक ईव्ही वाहन की सवारी की.

ये पहली बार है कि प्रदेश का कोई सीएम ईव्ही वाहनों का उपयोग करेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने कारकेड के वाहनों की संख्या को घटाकर पहले ही लगभग आधा कर चुके हैं. पहले वे 13 वाहनों के काफिले में चलते थे, लेकिन अब महज 7 वाहनों का काफिला ही कारकेड में शामिल किया गया है, जिसमें ये ईव्ही भी शामिल है. महेन्द्रा कंपनी की सफेद रंग की एक्सईव्ही 9ई एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसकी रेंज 500 किमी से अधिक है. इस ईव्ही का नंबर भी बेहद दिलचस्प

है. इसे एमपी02 वीबी-2047 नंबर मिला है. दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने का संकल्प रखा है, विकसित भारत 2047 को ध्यान में रखते हुए ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम तैयार हो रहे हैं, वहीं आर्थिक विकास को रफ्तार भी इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसी विजन से प्रेरित होकर यह नंबर लिया गया है.

सुरक्षा मानकों पर खरा उतरने के बाद किया शामिल

इसी ईव्ही को सीएम के कारकेड में शामिल करने से पहले मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत् जांच एवं अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारिकी से परीक्षण करने के बाद शामिल किया गया है, जिससे ये सुरक्षा के मानकों पर खरा उतरे और इससे यात्रा सीएम के लिए सुरक्षित रहे.

ईव्ही का उपयोग हम सभी के लिए हितकारी

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईंधन की अधिकतम बचत करने और मितव्यतापूर्ण यात्रा के साधन अपनाने का संदेश दिया है. इससे देश एवं प्रदेश में ईंधन की बचत को बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री कहा कि हम सभी का यह दायित्व है कि ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्थक प्रयास करें. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है. ये ईवी न केवल ईंधन की बचत करते हैं, बल्कि पर्यावरण के लिए भी अत्यंत लाभकारी साबित होते हैं.

मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने समीक्षा के दौरान कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 3 जून. मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य समय-सीमा में पूरा करें. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग दीपक सिंह ने यह बात पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा के दौरान कही.

सिंह ने जिलेवार लंबित दावे-आपत्तियों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य में पूरी पारदर्शिता रहनी चाहिए.

सिंह ने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण के संबंध में जो भी कार्यवाही करें, उसकी जानकारी स्टेरिंग कमेटी की बैठक के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में जरूर लायें. उन्होंने वर्किंग और नानवर्किंग ईव्हीएम की जानकारी देने के निर्देश भी दिये.

उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची को नियत समय पर जिले की वेबसाइट पर अपलोड करें. बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग शहडोल से वीसी में शामिल हुए.

एक नजर में

पुलिस ने 30 लाख के मोबाइल बरामद किए

शिवपुरी. जिले की साइबर सेल ने गुम और चोरी हुए 120 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को वापस सौंप दिए. बरामद मोबाइल फोनों की अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि साइबर सेल ने तकनीकी विश्लेषण और ट्रैकिंग के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तथा महाराष्ट्र से मोबाइल फोन बरामद किए हैं. उन्होंने बताया कि बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन गुम अथवा चोरी हो गए थे. साइबर सेल की कार्रवाई के बाद इनकी पहचान कर संबंधित लोगों को वापस सौंप दिया गया.

छात्रा की हत्या के विरोध में चक्काजाम समाप्त

भिण्ड. जिले के झांकरी चौकी क्षेत्र की एक नाबालिग छात्रा के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में ग्रामीणों द्वारा किया गया चक्काजाम देर रात प्रशासन और पीड़ित परिवार के बीच सहमति बनने के बाद समाप्त हो गया. इसके बाद आज छात्रा का अंतिम संस्कार किया गया. छात्रा का शव क्षेत्र में पहुंचने के बाद ग्रामीणों और समाज के लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया था. प्रदर्शनकारी पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता, शस्त्र लाइसेंस तथा मामले की त्वरित सुनवाई की मांग कर रहे थे.

फिर बदला सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म का नियम

01 से 8वीं कक्षा तक खातों में पैसे की जगह अब सीधे मिलेगी ड्रेस

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 03 जून. प्रदेश सरकार के नए फैसले के तहत छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में पैसा भेजने की बजाय उन्हें सीधे रेडीमेड यूनिफॉर्म खरीदकर दी जाएगी. वहीं विभाग अब राज्य के करीब 55 लाख बच्चों को सीधे यूनिफॉर्म देने की तैयारी में है. जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रभावी करने की उम्मीद है.

2017 से अब तक 5 बार बदली यूनिफॉर्म वितरण की प्रक्रिया

2017 तक पहले बच्चों के खाते में दो जोड़ी यूनिफॉर्म के लिए 400 रुपये दिए जाते थे. 2018 में राशि में बढ़ोतरी कर 600 रुपये कर दिया गया. वहीं इसके कुछ समय बाद पैसे की जगह यूनिफॉर्म देने का निर्णय हुआ और वर्ष 2019 व 2020 में पंचायत विभाग के अंतर्गत आने वाले महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से यूनिफॉर्म तैयार कराई गई. लेकिन इन यूनिफॉर्म के साइज छोटे-बड़े निकलने की शिकायतें आईं. इसके बाद कोविड-19

▶ सत्र 2026-27 से लागू होने की है उम्मीद

महामारी के दौरान लॉकडाउन और फंड जारी होने में हुई देरी के चलते यह स्व सहायता समूह वाला मॉडल पूरी तरह चरमरा गया.

2021 से डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सिस्टम हुआ लागू

स्व सहायता समूह मॉडल के असफल होने के बाद सरकार ने 2021 में एक बार फिर बच्चों के बैंक खातों में सीधे 600 रुपये ट्रांसफर करने की व्यवस्था शुरू की. जिससे अभिभावक खुद कपड़ा खरीदकर स्थानीय दर्जियों से ड्रेस सिलवा सकें. पुरानी व्यवस्था में न तो कपड़ों की क्वालिटी सुनिश्चित हो पा रही थी और न ही एकरूपता. जिससे कई बच्चे स्कूलों में बेमेल या बिना तय मापदंड के कपड़े पहनकर आने लगे.

पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम हो तैयार

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीद के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाया जाए, ताकि हर जिले में समय पर यूनिफॉर्म पहुंच सके. इससे सरकारी धन के उपयोग में पारदर्शिता आएगी और ग्रामीण व जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों में आर्थिक असमानता दूर होकर समानता और अनुशासन की भावना पैदा होगी.

डीजीपी मकवाणा ने घोषित किए प्रतिष्ठित पुरस्कार

उत्कृष्ट पुलिसकर्मियों का होगा सम्मान

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 जून. पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश पुलिस के प्रतिष्ठित के.एफ. रुस्तमजी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है.

इन पुरस्कारों के माध्यम से पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शित असाधारण साहस, नेतृत्व क्षमता, कर्तव्यनिष्ठा और पेशेवर उत्कृष्टता को सम्मानित किया जाएगा. मध्यप्रदेश पुलिस का यह पुरस्कार बल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है. इसे उन अधिकारियों

एवं कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने दस्यु उन्मूलन, नक्सल विरोधी अभियानों, सांप्रदायिक तनाव की स्थितियों तथा गंभीर कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियों का सामना करते हुए उल्लेखनीय साहस और नेतृत्व का परिचय दिया है. पुरस्कार तीन श्रेणियों परम विशिष्ट, अति विशिष्ट और विशिष्ट में प्रदान किए जाते हैं. इसका उद्देश्य उत्कृष्ट सेवाओं को पहचान देना तथा पुलिस संगठन में समर्पण, साहस और श्रेष्ठ कार्य संस्कृति को प्रोत्साहित करना है. इसके अतिरिक्त अति विशिष्ट श्रेणी में छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विशिष्ट श्रेणी में 35 पुलिसकर्मियों को पुलिसिंग, खुफिया सूचना संकलन, साइबर जांच, आतंकवाद निरोधक अभियानों और नक्सल विरोधी गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा.

सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई...

पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए पुलिस महानिदेशक मकवाणा ने कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश पुलिस की पेशेवर दक्षता, जनसेवा के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का प्रतीक है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सम्मानित अधिकारी और कर्मचारी भविष्य में भी अपनी सेवाओं से पुलिस बल की प्रतिष्ठा को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे.

वर्ष 2022-23 के लिए अति विशिष्ट श्रेणी में सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना तथा उप निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला को सम्मानित किया गया है. वहीं विशिष्ट श्रेणी में विशेष अभियान, अपराध अनुसंधान, साइबर अपराध, महिला सुरक्षा तथा नक्सल विरोधी इकाइयों सहित विभिन्न शाखाओं के 24 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चयनित किया गया है. वर्ष 2023-24 के लिए परम विशिष्ट श्रेणी का सम्मान पूर्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाखा, उप पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह सिकरवार, निरीक्षक कंचन ठाकुर तथा एटीएस के राजेश कुमार और कमलेश सिंह को प्रदान किया गया है.

निरीक्षण के बाद हटाए गए होमगार्ड सैनिक और अधीक्षक

उज्जैन. मध्यप्रदेश बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष निवेदिता शर्मा और सदस्य सोनम निनामा के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान उज्जैन स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में बच्चों द्वारा की गई दुर्व्यवहार की शिकायत के बाद एक होमगार्ड सैनिक और अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है. आयोग की अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता शर्मा और सदस्य श्रीमती निनामा ने जिले के दो दिवसीय प्रवास के दौरान बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया. इस दौरान वहां रह रहे बच्चों ने एक होमगार्ड सैनिक पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया.

रेल कारखाना परिसर में निकली साइकिल रैली

भोपाल,3 जून. विश्व पर्यावरण दिवस अभियान-2026 एवं विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर निशातपुरा स्थित सवारी डिब्बा पुनर्निर्माण कारखाना परिसर में पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया. रैली का उद्देश्य कर्मचारियों एवं आमजन को प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और साइकिल उपयोग के प्रति जागरूक करना था. रैली का शुभारंभ कारखाना परिसर से हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों, शाखाओं, अनुभागों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. रैली प्रशासनिक भवन परिसर से तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान तक निकाली गई.

कार्यक्रम की शुरुआत में सहायक कार्मिक अधिकारी एम.एल. मीणा ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की.

तीन मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो की मौत

सिवनी. जिले के धनौरा थाना क्षेत्र में तीन मोटरसाइकिलों की टक्कर में दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि छह अन्य घायल हो गए. पुलिस सूत्रों के अनुसार कहानी-धनौरा मार्ग पर थांवरी गांव के समीप दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे तीन मोटरसाइकिलें आमने-सामने टकरा गईं. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दो लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई. धनौरा थाना प्रभारी मनीष बंसोड़ ने बताया कि मृतकों की पहचान सुमान सिंह उइके निवासी ग्वारी धनौरा और गौतम उइके निवासी मठदेवरी, थाना लखनादौन के रूप में हुई है. दुर्घटना में घायल छह लोगों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धनौरा पहुंचाया गया.

जल संरक्षण को आंदोलन बना रही सरकार

वर्षाकाल के पूर्व जल संरचनाओं के आवश्यक-सुरक्षात्मक कार्य पूरे करें

▶ मंत्री सिलावट ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की

भोपाल, 3 जून. जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा है कि प्रदेश में जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में 'जल गंगा संवर्धन' तथा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान गांव-गांव और नगर-नगर में चलाए जा रहे हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. वल्लभ भवन में विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री

सिलावट ने निर्देश दिए कि वर्षाकाल से पहले सभी बांधों, नहरों, तालाबों और अन्य जल संरचनाओं की मरम्मत एवं सुरक्षात्मक कार्य हर हाल में पूरे किए जाएं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी. बैठक में विभिन्न कछारों की सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. मंत्री ने आगामी 15 दिनों में सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए. साथ ही सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मंत्री सिलावट ने कहा कि जल स्तर की सतत मॉनिटरिंग की जाए और गेट खोलने या जलस्तर बढ़ने की स्थिति में प्रशासन, पुलिस और आम नागरिकों को समय पर सूचना दी जाए. पिछले वर्षों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए. उन्होंने नाव, गोताखोर, लाइफ जैकेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया.

आरोप | सरकारें किसानों की परेशानियों को दूर करने के बजाय प्रचार अभियानों में व्यस्त

किसानों की अनदेखी पर कुणाल का हमला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 3 जून. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी ने किसानों की समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारें किसानों की वास्तविक परेशानियों को दूर करने के बजाय केवल प्रचार आधारित अभियानों में व्यस्त हैं.

भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कुणाल चौधरी ने निमाड़ क्षेत्र में हाल ही में आए आंधी-तूफान से हुई तबाही के वीडियो साक्ष्य प्रस्तुत किए. उन्होंने बताया कि बुरहानपुर, खंडवा और खरगोन जिलों के कई गांवों में केले की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं.

कुणाल चौधरी ने प्रदेश में केले की फसल के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना नहीं होने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय कृषि मंत्री के संसद में दिए गए उत्तर से स्पष्ट है कि वर्तमान और पूर्ववर्ती राज्य सरकारों ने किसानों को इस बीमा का लाभ दिलाने के लिए कोई पहल नहीं की.

शाहपुरा, खापा, धमनगांव, लोनी, बहादुरगढ़, बोलाना और दरियापुर सहित अनेक गांवों में तेज हवाओं के कारण केले के बागान धराशायी हो गए, जिससे किसानों को 150 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. उन्होंने रायसेन में शुरू किए गए 'खेत बचाओ अभियान' की आलोचना करते हुए कहा कि मिट्टी पूजन और प्रतीकात्मक कार्यक्रम किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते. किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, सस्ती खाद, पर्याप्त बिजली, सिंचाई सुविधाएं और बढ़ते कर्ज से राहत की आवश्यकता है. उन्होंने राज्य सरकार की ऑनलाइन खाद वितरण और ई-टोकन व्यवस्था को भी किसान विरोधी बताते हुए कहा कि इससे किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा 3, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, महाराणा प्रताप नगर, जोन-1, भोपाल से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स से मुद्रित. संपादक दिलीप झा*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-4939198, ईमेल-bhopalnav@gmail.com RNI Reg. No. 35046/56 डाक पंजीयन क्रमांक M.P/B.P.L/711/2012-14